

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 309 | श्री विजयपुरम, शनिवार, 21 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए



दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय उप राज्यपाल ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

'PANI' परियोजना के तहत आठ द्वीपों को समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली केबल प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव

4जी संतृप्ति योजना एवं भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगी इंटरनेट सुविधा

श्री विजयपुरम, 20 नवंबर।

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सचिव श्री अमित अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में द्वीपसमूह में दूरसंचार एवं डिजिटल संपर्क व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ द्वीपों तक बेहतर संचार सुविधाएं पहुंचाने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान केंद्र सरकार की प्रस्तावित **'PANI'** परियोजना के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समुद्र के भीतर केबल नेटवर्क (सबमरीन केबल नेटवर्क) के विस्तार को गति देने पर विशेष चर्चा हुई। इस परियोजना के तहत डिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चावरा, तेरेसा, कछाल, ननकौड़ी एवं लिटिल निकोबार सहित आठ द्वीपों को समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली केबल प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे इन द्वीपों में मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में भी निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

विशेष रूप से, वर्तमान में चेन्नई से संचालित सीएएनआई **(CANI)** समुद्र के भीतर केबल नेटवर्क में किसी प्रकार की बाधा अथवा क्षति होने की स्थिति में ओडिशा के पुरी से प्रस्तावित पीएएनआई **(PANI)** नेटवर्क एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा। इससे इंटरनेट सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी तथा



दूरसंचार व्यवस्था की विश्वसनीयता और सुदृढ़ होगी।

माननीय उप राज्यपाल ने प्रस्तावित नेटवर्क में डुगोंग क्रीक को भी शामिल करने तथा वहां केबल लैंडिंग स्टेशन **(CLS)** स्थापित करने का सुझाव दिया। इससे नेटवर्क का विस्तार और अधिक व्यापक होगा तथा द्वीपसमूह की संचार व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत संचालित 4जी संतृप्ति योजना की समीक्षा के दौरान द्वीपसमूह के ऐसे 87 गांवों को, जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता देते हुए 4जी नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इस पहल से दूरस्थ एवं दुर्गम





क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क तथा उच्च गति की इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्क सुविधा से वंचित 174 गांवों तक फाइबर के माध्यम से घर–घर तक इंटरनेट संपर्क **(FTTH)** उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 70 ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सात जनजातीय परिषदों में से चार को भी संचार नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है तथा शेष तीन को शीघ्र ही इस सुविधा से जोड़ने की योजना है। माननीय उप राज्यपाल ने शेष वंचित गांवों तक फाइबर आधारित नेटवर्क पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने पर विशेष बल दिया।

बैठक में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रत्येक द्वीप एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र तक विश्वसनीय दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इससे स्थानीय निवासियों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन सुविधाओं तथा आपातकालीन संचार व्यवस्था का बेहतर लाभ मिल सकेगा।

बैठक में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स) सुश्री पूर्वा गर्ग, उप राज्यपाल की सचिव सुश्री ज्योति कुमारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निर्वाचित प्रधानों की मांग पर माननीय उप राज्यपाल ने ग्राम पंचायतों के लिए 18.62 करोड़ रूपए का मिलान अनुदान किया स्वीकृत

श्री विजयपुरम, 20 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की ग्राम पंचायतों को मिलान अनुदान जारी करने की माँग निर्वाचित प्रधानों द्वारा शिष्टाचार भेंट के दौरान और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद द्वारा राज्य स्तरीय 'दिशा' बैठक में उठाई गई थी, इस विषय को प्राथमिकता देते हुए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने 18.62 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की।







अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद् के अध्यक्ष श्री उमर जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लोक निवास, श्री विजयपुरम में शिष्टाचार भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया। ज़िला परिषद विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, फरारगंज में स्मार्ट कक्षाओं के उद्घाटन एवं तीन नवीन कक्षाओं के आगामी शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया तथा संस्कृति युवा संस्थान, जयपुर के अध्यक्ष पं. सुरेश एम. मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की।

सेंट मेरीज़ स्कूल की 30वीं वर्षगांठ (पर्ल जुबली) समारोह का भव्य आयोजन, माननीय उप राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन

भारतीय पारिवारिक मूल्यों, उच्च शिक्षा के विस्तार एवं विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर दिया ज़ोर







श्री विजयपुरम, 20 नवंबर।

माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने आज श्री विजयपुरम स्थित सेंट मेरीज़ स्कूल की 30वीं वर्षगांठ (पर्ल जुबली) समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय उप राज्यपाल ने भारतीय पारिवारिक संस्कृति, परंपराओं एवं नैतिक मूल्यों के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और उनमें अच्छे संस्कार विकसित करने की पहली पाठशाला है। शिक्षा के साथ–साथ बच्चों में अनुशासन, बड़ों के प्रति सम्मान, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं पारिवारिक मूल्यों का विकास भी अत्यंत आवश्यक है।

माननीय उप राज्यपाल ने एलजी राहत कोष में 1 लाख रूपए का योगदान प्रदान करने के लिए सेंट मेरीज़ स्कूल के प्रबंधन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के हित में अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किए जाने की भी सराहना की तथा इसे ज़रूरतमंद एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की एक सराहनीय पहल बताया।

द्वीपसमूह में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में बीबीए पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा भविष्य में इसी प्रकार के अन्य उच्च स्तरीय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी द्वीपसमूह में शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने से वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर भविष्य बना सकेंगे।

माननीय उप राज्यपाल ने आगे बताया कि प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों, विद्वानों एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं

शेष पृष्ठ 4 पर









अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से लोक निवास, श्री विजयपुरम में शिक्षक कल्याण फाउंडेशन, दिल्ली के प्रदेश सचिव श्री नवीन गुप्ता जी एवं एनसीईआरटी, दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ. रेजाउल करीम जी ने शिष्टाचार भेंट कर अण्डमान में शिक्षकों के प्रशिक्षण की विस्तृत योजना तथा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले शैक्षणिक उत्कृष्टता कार्यक्रम पर चर्चा की तथा क्रॉस टाउन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री राहिल गुप्ता ने भी शिष्टाचार भेंट की।









अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने एनएचआईडीसीएल की राज्य विशिष्ट स्नातक योजना (एसएसजीएस) के तहत एसोसिएट (टेक्नीकल) पद पर चयनित द्वीपसमूह के 07 स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह चयन द्वीपवासियों के रोज़गार में बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा।

सेंट मेरीज़ स्कूल की 30वीं वर्षगांठ (पर्ल जुबली)

————————पृष्ठ 1 का शेष







लेकर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य द्वीपसमूह के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए मार्गदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन प्रयासों से यहां के विद्यार्थी देश के अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे तथा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन विशेषज्ञ एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का नाम रोशन करेंगे।

अंत में, माननीय उप राज्यपाल ने सेंट मेरीज़ स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विद्यालय की 30 वर्षों की गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा पूर्ण करने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी शिक्षा, संस्कार एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जारी रखने की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर माननीय सांसद (लोकसभा), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह श्री विष्णु पद राय, पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता के. सुगथन, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष, मलनकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च, चेन्नई परम श्रद्धेय डॉ. गीवर्गीस मार फिलॉक्सेनोस, उपाध्यक्ष, एस.एम.सी.ई.एस. फादर शिनु के. थॉमस सहित शिक्षकगण, अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।







अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से लोक निवास, श्री विजयपुरम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भाजपा प्रभारी श्री जे.पी. भाई जी एवं अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी ने शिष्टाचार भेंटकर डिगलीपुर और आसपास क्षेत्र की खराब सड़क तथा गैस सिलेंडर की कमी और कदमतला और उत्तरा में पानी की समस्या पर चर्चा की। उपरोक्त के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समस्या के निवारण के लिए कहा गया।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न

मायाबंदर, 20 नवंबर।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला योजना समिति (डीपीसी) की दो दिवसीय बैठक 18 एवं 19 नवंबर, 2026 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री विष्णु पद राय, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला परिषद के अध्यक्ष श्री आर. अलगस्वामी, उत्तर व मध्य अण्डमान के उपायुक्त श्री सुशांत पधा, भा.प्र.से., तथा ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्ण चैतन्य सहित ज़िला परिषद के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दो दिवसीय बैठक के दौरान ज़िला योजना समिति ने उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले से संबंधित विभिन्न विकासात्मक प्रस्तावों, क्षेत्रवार आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर ज़िला परिषद के सदस्यों ने अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों की प्रमुख विकासात्मक आवश्यकताओं एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को समिति के समक्ष रखा। उन्होंने स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा उचित कदम उठाए जाने पर विशेष बल दिया।

विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने विभागों से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं एवं आगामी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। समिति ने इन प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करते हुए वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए ज़िला कार्ययोजना की अनुशंसा की। इस कार्ययोजना में उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के विभिन्न विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की योजनाओं एवं विकास प्रस्तावों को शामिल किया गया है।

बैठक में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, ज़िला प्रशासन एवं विभिन्न



विभागों के अधिकारियों के बीच सार्थक विचार–विमर्श और समन्वय का अवसर प्राप्त हुआ। इससे ज़िला स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण में स्थानीय प्राथमिकताओं तथा आम जनता की आवश्यकताओं को उचित महत्व सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक का सफल आयोजन ज़िले में विकेंद्रीकृत एवं जनभागीदारी आधारित नियोजन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समिति की अनुशंसाओं से विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने, विभिन्न विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में संतुलित विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की उम्मीद है। बैठक का समापन सकारात्मक वातावरण में हुआ। इस अवसर पर सभी संबंधित पक्षों ने वित्तीय वर्ष 2027–28 की अनुशंसित ज़िला कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास और जनकल्याण के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अण्डमान–निकोबार के पांच स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्रमाणन दिलाने की पहल

श्री विजयपुरम, 20 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को विश्वस्तरीय खगोल–पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने कोयंबटूर स्थित मेसर्स सीएसटीईआरसी टेक्नो साइंस एलएलपी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत द्वीपसमूह के पांच चिन्हित स्थलों के लिए डार्कस्काई इंटरनेशनल के अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेसेज (आईडीएसपी) कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण के आवेदन तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमाणन के प्रारंभिक चरण के लिए चयनित पांच स्थल निम्नलिखित हैं
– प्रभाष मुंडी (लिटिल अण्डमान)
– बालूडेरा बीच (बाराटांग)
– चिड़ियाटापू (दक्षिण अण्डमान)
– शोल बे–19 (दक्षिण अण्डमान)
– रामनगर बीच (डिगलीपुर)

यह पहल प्रशासन की समर्पित खगोल–पर्यटन नीति का एक प्रमुख आधार स्तंभ है, जो ज़िम्मेदार खगोल–पर्यटन, अंधकारमय रात्रि आकाश के संरक्षण तथा रात्रिकालीन पर्यावरण के सतत प्रबंधन के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है। प्राकृतिक रूप से स्वच्छ एवं निर्मल बोर्टल श्रेणी–1 के अंधकारमय आकाश, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण की न्यूनतम मात्रा तथा भूमध्य रेखा के निकट विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण, जहां उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों के खगोलीय पिंडों को देखा जा सकता है, ये द्वीप खगोलीय अवलोकन के लिए असाधारण प्राकृतिक संभावनाएं रखते हैं।

सीएसटीईआरसी टेक्नो साइंस एलएलपी लगभग 8 से 10 सप्ताह की अनुमानित अवधि में विशेष तकनीकी एवं आवेदन–विकास संबंधी सहायता प्रदान करेगी। कार्य के दायरे में रात्रि आकाश का आधारभूत



आकलन, क्षेत्र स्तर पर वैज्ञानिक अवलोकन, कृत्रिम प्रकाश स्रोतों की सूची तैयार करना, स्थलों की सीमाओं का मानचित्रण, फोटोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण तथा डार्कस्काई इंटरनेशनल को प्रथम चरण के पात्रता आवेदन औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्रशासन की अग्रणी खगोल–पर्यटन नीति के अंतर्गत व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। इन प्रयासों में पहले से ही प्रमुख खगोल–पर्यटन स्थलों की आधिकारिक अधिसूचना जारी करना, 200 से अधिक स्थानीय खगोल–मार्गदर्शकों को विशेष प्रशिक्षण देना, पूरे द्वीपसमूह में तारों को निहारने के उत्सव आयोजित करना तथा आरएएमपी योजना के तहत दूरबीनों की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इन पांच स्थलों के लिए डार्क स्काई इंटरनेशनल का प्रमाणन प्राप्त होने से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को विश्व के प्रमाणित अंधकारमय आकाश वाले पर्यटन स्थलों के मानचित्र पर स्थान मिलेगा। इससे उच्च मूल्य वाले, कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले विशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस सुविधा हेतु चेन्नई के अपर निदेशक नामित

श्री विजयपुरम, 20 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की जानकारी एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सूचित किया जाता है कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच) द्वारा **WP-CT/27/2026** (भारत संघ बनाम श्री रमेश चंदर नाथ) तथा **WP-CT/37/2026** (भारत संघ बनाम श्री वी.पी. बाबू) में दिनांक 05.10.2026 को पारित आदेशों के अनुपालन में एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव के अनुरोध के अनुसरण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ईएचएस अनुभाग) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या **Misc–53/2026–CGHS9HQ)/C&P Section/EHS** दिनांक 19.11.2026 के माध्यम से चेन्नई स्थित सीजीएचएस के अपर निदेशक को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सीजीएचएस लाभार्थियों एवं पेंशनभोगियों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है।

नामित नोडल अधिकारी निम्नलिखित प्रमुख कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे:
– सीजीएचएस कार्ड जारी करना: प्रचलित सीजीएचएस नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
– शिकायतों का निवारण: सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने में पेंशनभोगियों को होने वाली शिकायतों एवं कठिनाइयों का समाधान करना।
– विभागों के बीच समन्वय: पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए योजना के लाभों का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के साथ निकट समन्वय स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने चेन्नई स्थित सीजीएचएस के अपर निदेशक से अण्डमान तथा निकोबार के पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर एवं ईमेल संबंधी विवरण प्रसारित करने का अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस संबंध में जारी सूचना का संज्ञान लें।



कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाएं 23 नवंबर से

श्री विजयपुरम, 20 नवंबर

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 2026 (प्रश्नपत्र–1), दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 2025 (प्रश्नपत्र–2) तथा कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) परीक्षा, 2026 का आयोजन 23 से 28 नवंबर तथा 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा। उप सचिव (आर एंड ई) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई–प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **https://ssc.gov.in/ |https://sscer.org** पर निर्धारित परीक्षा तिथि से 3–4 दिन पूर्व उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

श्री विजयपुरम, 20 नवम्बर।

दक्षिण अण्डमान प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामीण इलाकों में शनिवार, 21 नवंबर, 2026 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार, सीपीघाट साइट कार्यालय से जुड़े क्षेत्र में एच.टी. और एल.टी. लाइनों के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते यह शटडाउन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सीपीघाट, बम्बूनाला और नयाशहर क्षेत्र शामिल हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य मौसम की अनुकूल स्थिति पर निर्भर करेगा। हालांकि, यदि मरम्मत का काम निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाता है, तो बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। विद्युत विभाग ने इस कटौती से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

पुलिस मुख्यालय में पॉश संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित

श्री विजयपुरम, 20 नवम्बर।

पुलिस मुख्यालय, श्री विजयपुरम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आज कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 'राइट्स फॉर ऑल' की अध्यक्षा तथा प्रमाणित पॉश मास्टर ट्रेनर एवं सलाहकार श्रीमती रुबीना सिद्दीकी द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुमा मड्डा, पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय), ने संसाधन व्यक्ति श्रीमती रुबीना सिद्दीकी का हार्दिक स्वागत किया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ दीं।

सत्र के दौरान, संसाधन व्यक्ति ने प्रतिभागियों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (पॉश) के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाया। उन्होंने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध, नियोक्ताओं और कर्मचारियों की ज़िम्मेदारियाँ, आंतरिक समिति की भूमिका और कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र, गोपनीयता तथा एक सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण बनाए रखने का महत्व जैसे मामले शामिल थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में पेशेवर आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान तथा कार्यस्थल पर अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के महत्व को भी रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों को एक सुरक्षित, समावेशी और उत्पीड़न–मुक्त कार्यस्थल के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और इसका समापन सभी कर्मियों के लिए एक सम्मानजनक, सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में सामूहिक उत्तरदायित्व पर ज़ोर देने के साथ हुआ।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

आत्मनिर्भर भारत की नई उपलब्धिः केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन, भोपाल में बनेगी 300 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक लैब

नई दिल्ली, 20 नवम्बर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में बर्ड लू (H5N1) की देश की पहली स्वदेशी चिकन वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की। इस वैक्सीन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर भोपाल में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत महज 1 से 2 रुपए होगी, जिससे छोटे पोल्ट्री किसानों को भी अपने मुर्गियों के झुंड को संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह वैक्सीन बर्ड लू के H5N1 वेरिएंट के लिए दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन बताई गई है।



विदेश में भारत को बदनाम करने वालों पर साधा निशाना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने विदेशों में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं, वैज्ञानिकों और उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया में जाकर अपने ही देश को बदनाम करते हैं, उन्हें आज का आत्मनिर्भर और विकसित भारत देखना चाहिए। देश की संवैधानिक संस्थाओं, सेना, वैज्ञानिकों और आम लोगों के परिश्रम पर सवाल उठाना देश के सामर्थ्य को कमतर आंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड महामारी के दौरान महज नौ महीने में दो स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई थी। अब बर्ड लू की स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर भारत की तकनीकी और अनुसंधान क्षमता का परिचय दिया है।

भोपाल में 300 करोड़ रुपए से बनेगी अत्याधुनिक प्रयोगशाला

भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (निषाद) की उपलब्धियों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 300 करोड़ रुपए की लागत से नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोपाल का यह संस्थान देश के लिए गौरव का केंद्र बन गया है। चौहान ने बताया कि पहले वैक्सीन का लोकार्पण दिल्ली से करने की योजना थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जिन वैज्ञानिकों ने भोपाल में दिन–रात मेहनत करके इसे विकसित किया है, उनके बीच ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

पशु किसानों के चलते–फिरते एटीएम, बीमारियों से होता है 56 हजार करोड़ रुपए का नुकसान

पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए चौहान ने कहा कि पशु किसानों के लिए चलते–फिरते एटीएम की तरह हैं। वे खेती के साथ नियमित आमदनी का माध्यम बनते हैं। उन्होंने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पशुपालन का योगदान 14% और पोल्ट्री क्षेत्र का योगदान 1% है। उन्होंने विभिन्न पशु रोगों से होने वाले आर्थिक नुकसान का जिक्र करते हुए बताया कि खुरपका–मुंहपका रोग से सालाना औसतन 22,000 करोड़ रुपए, लंपी वायरस से 20,000 करोड़ रुपए, ब्रूसेलोसिस से 9,212 करोड़ रुपए और भेड़–बकरियों में फैलने वाले पीपीआर रोग से 4,683 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इन बीमारियों से कुल मिलाकर करीब 56,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी टीकों के विकास से पशुपालकों को इस नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।

1 से 2 रुपए में मिलेगी वैक्सीन, 2006 से अब तक 500 से अधिक प्रकोप

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत में बर्ड लू का पहला प्रकोप वर्ष 2006 में महाराष्ट्र के नवापुर में सामने आया था। उस दौरान करीब 10 लाख मुर्गियों की मौत हुई थी और संक्रमण को रोकने के लिए बड़ी संख्या में मुर्गियों को मारकर दफनाना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2021 में करीब 9 लाख और इस वर्ष भी 2 लाख मुर्गियों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से अब तक देश में बर्ड लू के 500 से अधिक प्रकोप सामने आ चुके हैं। इससे पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस संक्रमण के स्तनधारी पशुओं और मनुष्यों तक फैलने का खतरा भी बना रहता है। नई स्वदेशी वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1 से 2 रुपए रखी गई है, ताकि छोटे पोल्ट्री किसान भी इसे आसानी से खरीद सकें और अपने व्यवसाय को सुरक्षित रख सकें।

टीकाकरण अभियान से पशु रोगों पर नियंत्रण की दिशा में प्रगति

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत खुरपका–मुंहपका रोग से बचाव के लिए अब तक 147 करोड़ 16 लाख मुत टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान से ब्रूसेलोसिस पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में लंपी त्वचा रोग के प्रकोप के दौरान 32 लाख 80 हजार पशु संक्रमित हुए थे और 1 लाख 86 हजार पशुओं की मौत हुई थी। उस समय हिसार और इज्जतनगर के वैज्ञानिकों ने 'लंपी प्रोवैकइंड' वैक्सीन विकसित की थी। चौहान ने कहा कि भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इससे पहले भी गंबेरो वैक्सीन, ब्रूसेला एबॉर्टस एस–19 डेल्टा वैक्सीन, क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के स्वदेशी टीके विकसित कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

छुट्टियां छोड़कर वैज्ञानिकों ने की महीनों तक रिसर्च

वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के समर्पण की सराहना करते हुए चौहान ने उन्हें इस उपलब्धि का असली नायक बताया। उन्होंने वैज्ञानिकों डॉ. एस. नागराजन, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. सी. तोश, डॉ. एच. वी. मुरगकर, डॉ. अनिकेत सान्याल, डॉ. सेंथिल कुमार डी., डॉ. नवीन कुमार और डॉ. योगीशाराध्या आर. के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने शनिवार और रविवार की छुट्टियां लिए बिना कई महीनों तक लगातार शोध किया। प्रयोगशाला में लागू कड़े जैव–सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें घर जाने से पहले और बाद में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उन्हें प्रतिदिन करीब 120 लीटर पानी से स्नान करना होता था। शोध के दौरान वे अपने घरों में पालतू पशु भी नहीं रख सकते थे। चौहान ने वैज्ञानिकों के समर्पण और कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान देश के लिए प्रेरणादायक है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक रहे मौजूद

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के युवा, खेलकूद एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा और भोपाल की महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इनके अलावा राकेश शर्मा, नरेश मेवाड़ा, राकेश जादौन, राजेश चौकसे और छाया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के निदेशक डॉ. अनिकेत सान्याल सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। (इनपुटः पीआईबी)

1,100 से अधिक विद्यार्थी 'युवा सोमनाथ यात्रा' पर रवाना, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली, 20 नवम्बर

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 'युवा सोमनाथ यात्रा' को रवाना किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस विशेष यात्रा में विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के 1,100 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना तथा सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना है।

आक्रमणों के बावजूद कायम रही सोमनाथ की विरासत

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि एक हजार वर्षों में बार–बार हुए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। पिछली पीढ़ियों ने न केवल अपनी आस्था की रक्षा की, बल्कि देश की समृद्ध परंपराओं और विरासत को भी सहेजकर रखा। सोमनाथ का इतिहास भारत की आस्था, दृढ़ता और सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाता है।

युवाओं से विरासत पर गर्व करने का आह्वान

शेखावत ने कहा कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के संघर्ष और जीवटता के इतिहास को समझने तथा इसकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों को भारत की बौद्धिक संपदा, स्थापत्य विरासत और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों ने दुनिया को प्रभावित किया है और आज भी कर रही हैं।

35 हजार से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत अब तक 35,000 से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन कर चुके हैं। इस पहल के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तथा भारतीय विरासत में इसके विशिष्ट स्थान को रेखांकित किया जा रहा है।

17 राज्यों के श्रद्धालुओं ने किए सोमनाथ के दर्शन

संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव समर नंदा ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत 17 राज्यों के श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 11 मई 2026 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। युवा सोमनाथ यात्रा युवा पीढ़ी को मंदिर के समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।

भक्ति संगीत और गार्ड ऑफ ऑनर ने बढ़ाई कार्यक्रम की गरिमा

रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले 'साधो बैंड' ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। इससे स्टेशन का वातावरण आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण हो गया। वहीं, एनसीसी की महिला कैडेटों ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

25 नवंबर तक चलेगी विशेष रेल यात्रा

20 से 25 नवंबर 2026 तक निर्धारित यह विशेष रेलगाड़ी नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से गुजरात के वेरावल जंक्शन तक जाएगी। वेरावल पहुंचने के बाद विद्यार्थी सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे और वहां की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विरासत से परिचित होंगे। (इनपुटः पीआईबी)

भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, अमेरिकी नौसेना के पांचवें जहाज की कट्टुपल्ली में होगी मरम्मत

नई दिल्ली, 20 नवम्बर

अमेरिकी नौसेना का आपूर्ति पोत USNS Wally Schirra शुक्रवार को चेन्नई के पास एलएंडटी (L&T) के कट्टुपल्ली शिपयार्ड पहुंचा। यहां भारत–अमेरिका मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (MSRA) के तहत जहाज की मरम्मत की जाएगी। यह अमेरिकी नौसेना के मिलिट्री सीलिट कमांड (MSC) का हिस्सा है, जो दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य और सरकारी एजेंसियों को समुद्री परिवहन, रसद और विशेष समुद्री सहायता उपलब्ध कराता है।



कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज की मरम्मत का यह पांचवां अवसर है। इसे भारत के जहाज मरम्मत ढांचे और तकनीकी क्षमताओं पर अमेरिका के बढ़ते भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

2022 में शुरू हुआ था सहयोग

भारत और अमेरिका के बीच जहाज मरम्मत में सहयोग अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। उस समय USNS Charles Drew भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत कराने वाला अमेरिकी नौसेना का पहला जहाज बना था। इसके बाद मार्च 2023 में USNS Matthew Perry और जुलाई 2023 में USNS Salvor की मरम्मत की गई।

इन शुरुआती मरम्मत कार्यों के बाद अप्रैल 2023 में एलएंडटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच सहयोग को संस्थागत रूप दिया और शिपयार्ड को अमेरिकी नौसेना के जहाजों की यात्रा के दौरान आवश्यक मरम्मत (Voyage Repair) करने में सक्षम बनाया। इसके बाद दिसंबर 2024 में USNS Charles Drew दोबारा मरम्मत के लिए कट्टुपल्ली पहुंचा था।

संशोधित SOP के बाद पहला अमेरिकी जहाज

USNS Wally Schirra संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू होने के बाद मरम्मत के लिए भारत पहुंचने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज है। यह SOP जहाज के चालक दल के सदस्यों के भारत में प्रवेश और प्रस्थान की प्रक्रिया को सुगम बनाती है।

इसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आव्रजन ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के समन्वित प्रयासों से अंतिम रूप दिया गया। यह भारत में जहाज मरम्मत गतिविधियों को आसान बनाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को दर्शाता है।

जहाज मरम्मत केंद्र बनने की दिशा में भारत

USNS Wally Schirra का आगमन दिसंबर 2024 के बाद कट्टुपल्ली में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत गतिविधियों की बहाली का भी संकेत है। इससे अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत परिचालन को बढ़ावा देने और समुद्री औद्योगिक सहयोग मजबूत करने के भारत के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के पास रणनीतिक स्थिति, विकसित हो रहे शिपयार्ड ढांचे, कुशल कार्यबल और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के कारण भारत हिंद–प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। (इनपुट–MEA)

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनीं NCTE की राष्ट्रीय मेंटर, देशभर के शिक्षकों को करेंगी मेंटर

नई दिल्ली, 20 नवम्बर

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनीं NCTE की राष्ट्रीय मेंटर, देशभर के शिक्षकों को करेंगी मेंटर

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी को 'मित्र (MITRA & NMM)* पहल के तहत राष्ट्रीय मेंटर के रूप में शामिल किया है। इस पहल का उद्देश्य देशभर के स्कूली शिक्षकों को अनुभवी पेशेवरों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना और उनकी शिक्षण क्षमता को मजबूत करना है।

NCTE ने 18 नवंबर 2026 को अपने मुख्यालय से आयोजित एक ऑनलाइन सत्र के माध्यम से डॉ. बेदी को आधिकारिक तौर पर इस पहल में शामिल किया। इस दौरान उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई 'मित्र' पहल के उद्देश्य, ढांचे और इसके संभावित प्रभावों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर डॉ. किरण बेदी ने पहल की सराहना करते हुए इसे सेवानिवृत्त अधिकारियों, पेशेवरों और वरिष्ठ शिक्षाविदों के लिए समाज के प्रति योगदान देने का एक विश्वसनीय मंच बताया। उन्होंने इसके शिक्षक–केंद्रित . ष्टिकोण की भी प्रशंसा की। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि वह अगले महीने NCTE की इस पहल के तहत अपना पहला मेंटरिंग सत्र आयोजित करेंगी।

NCTE के अनुसार, डॉ. बेदी का व्यापक प्रशासनिक



अनुभव, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण देशभर के शिक्षकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गौरतलब है कि 'मेंटोरिंग इनिशिएटिव फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड असेसमेंट' (MITRA), जिसे पहले 'नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग' (NMM) के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCTE की एक पहल है। इसके माध्यम से अनुभवी मेंटर्स ऑनलाइन संवाद के जरिए सेवारत शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने पेशेवर कौशल को विकसित करने के साथ–साथ छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बना सकें। इस पहल के जरिए NCTE ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। (इनपुट–एजेंसी)

इतिहास के पन्नों में 21 नवम्बरः जब 'जय हिंद' के नारे वाला स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ

नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। इसपर 'जय हिंद' का नारा और भारतीय तिरंगा अंकित था। इसकी कीमत साढ़े तीन आने (पुराने समय में एक रुपये में 16 आना होते थे) थी। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता की पहचान बना। इसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर देश की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस टिकट को जारी करने का मकसद सिर्फ डाक सेवाओं के लिए इसका इस्तेमाल करना भर नहीं था बल्कि देश को ताजा–ताजा मिली स्वतंत्रता के संदेश को हर घर तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य था। यह टिकट आज भी डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए बेशकीमती है।



अन्य अहम घटनाएंः– 1877 – प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया।

1906 – चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई।

1921 – प्रिंस ऑफ वेल्स (सम्राट एडवर्ड अष्टम) बॉंबे (अब मुंबई) पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया।

1947 – आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया।

1956 – एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी।

1962 – भारत–चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया।

1963 – केरल के थुंबा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरु हुआ।

1986– मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया।

1999 – चीन द्वारा अपने प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान श्शेनझूश का प्रक्षेपण किया गया।

2001 – संयुक्त राष्ट्र ने अफ़ग़ानिस्तान में अंतरिम प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा।

2002 – मुस्लिम लीग (कायदे आजम) नेता जफ़रउल्ला ख़ान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित।

2005 – श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्नसिरी विक्रमनायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

2006 – भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।

2007–पैप्सिको चैयरमैन इंदिरा नूई को अमेरिकी इंडियन बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

2008 – प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की।

Directorate Of Health Services
Andaman & Nicobar Administration
Opening of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras in the Andaman and Nicobar Islands

F.No.9-10/DD(MED)/DHS/JANAUSHADI/2023/VOL III/144

SVP, dated 17th Oct, 2026

With a view to promoting the availability of quality generic medicines at affordable prices to the public, interested individuals, entrepreneurs, proprietors, NGOs, charitable organisations, trusts, societies, firms and private companies are encouraged to explore the opening of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) in the Andaman and Nicobar Islands.

Eligible applicants may apply directly through the official PMBI portal, subject to the prevailing scheme guidelines, eligibility conditions and statutory requirements. Applicants are required to fulfil the prescribed conditions, including availability of suitable premises, engagement of a qualified registered pharmacist, obtaining the requisite drug licence and submission of the documents required by PMBI.

Interested applicants may refer to the official website for the detailed guidelines, application procedure and prescribed documents:

Website: **https://www.janaushadhi.gov.in/apply-for-kendra**

For scheme-related information, applicants may contact PMBI through the contact details provided as under:

Chief Executive Officer,
Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI)
Office At: B-500, Tower B, 5th Floor, World Trade Center,
Nauroji Nagar, New Delhi- 110029.
Tel- 011-49431800

The opening and operation of each Kendra shall be subject to approval by PMBI and compliance with all applicable statutory and scheme requirements.

Sd/-
Director of Health Services
Directorate of Health Services
A&N Administration
Sri Vijaya Puram

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर (सीसीए)/ 2026–27/189

कार्य का नामः पंचायत समिति द्वारा नमूनाघर ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड संख्या 06 में मुख्य सड़क से जान खान के घर तक सीसी फुटपात का नवीनीकरण साथ ही फरीथ खान के घर से गुप्ता के घर तक ड्रेन का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 6,02,570/–, धरोहर राशि : रु. 12,051/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 27/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_26019_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

रुपये में लगातार पांचवें दिन तेजी, डॉलर के मुकाबले 65 पैसे मजबूत होकर 92.67 पर बंद



नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

रुपया में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और यह शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 65 पैसे मजबूत होकर 92.67 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी पूंजी के लगातार प्रवाह और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया सात महीने से अधिक समय बाद पहली बार 93 प्रति डॉलर के स्तर से ऊपर रहा।

रुपये में मजबूती का कारण कमजोर अमेरिकी मुद्रा और अमेरिका, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े शेयर के कमजोर पड़ने के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के भारतीय बाजार में लगातार निवेश है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के कमजोर रहने से रुपये को समर्थन मिला।

आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में दो से 13 तारीख के बीच नौ कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयरों में 84,290 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह लगातार दो महीने तक शुद्ध निकासी के बाद उनकी जोरदार वापसी है।

ताजा निवेश के बाद वर्ष 2026 में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की कुल निकासी घटकर करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये रह गई है। कुछ सप्ताह पहले यह लगभग तीन लाख करोड़ रुपये थी।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.25 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह मजबूत होकर 92.65 के उच्चस्तर तक गया और अंत में 65 पैसे मजबूत होकर 92.67 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। इसने 10 अप्रैल के बाद पहली बार 93 प्रति डॉलर का स्तर पार किया। उस दिन रुपया 92.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

रुपया बृहस्पतिवार को नौ पैसे मजबूत होकर 93.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। पिछले पांच लगातार कारोबारी सत्रों के दौरान शुक्रवार को रुपये में 1.6 प्रतिशत से अधिक की मजबूती आई है। इससे पहले 13 नवंबर को यह 94.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत गिरकर 103.87 पर रहा।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.82 प्रतिशत टूटकर 90.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। (इनपुट–भाषा)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सं. टीएन–डीबी/द.अ.म./2026–27/2606 दिनांक 18.11.2026

कार्यकारी अंभियंता, दक्षिण अण्डमान मण्डल अलोनिवि श्री विजयपुरम, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदा/बोली (CPWD–7 के रूप में) आमंत्रित करते हैं। यह ए – एन द्वीपों के अनुमोदित और योग्य ठेकेदारों के लिए है, चाहे उनका अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में नामांकन हो या न हो, केवल इस शर्त पर कि उन्हें संबंधित कार्य के निष्पादन का अनुभव हो जैसा सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल में निर्दिष्ट है और उन पर कोई नकारात्मक टिप्पणियाँ न हों। यह निम्नलिखित कार्य के लिए है :

NIT No. 11/EE/SAD/APWD/2025-26, Tender ID : 2026_APWD_26039_1

कार्य का नाम : डेयरी फार्म जंक्शन से स्कूल लाइन स्कूल तक सीसी ड्रेन का पुनर्निर्माण, जिसमें आरसीसी स्लैब और एमएस ग्रेटिंग शामिल है। अनुमानित लागत : रु. 1,77,55,346/–, अर्जित धनराशि : रु. 3,55,107/–, कार्य पूरा करने की अवधि : 10 महीने।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय : 02/12/2026 के अपराहन 1500 बजे।

निविदा फॉर्म और अन्य विवरण वेबसाइट **https://eprocure.andamannicobar.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कार्यकारी अंभियंता, दक्षिण अण्डमान मण्डल

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर(सीसीए)/2026–27/190

कार्य का नाम : पंचायत समिति द्वारा बम्बूलाट–।। ग्राम पंचायत के अंर्तगत वल्लुवर नगर में मुख्य गेट से मज़ार तक चेकर टाइल्स और हैंड रेलिंग के साथ सीसी फुटपात का नवीनीकरण।

अनुमानित लागत : रु. 16,51,683/–, धरोहर राशि : रु. 33,034/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 27/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट **https://eprocure.andamannicobar.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_26017_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

बोत्सवाना की मादा चीता ने जंगल में 4 शावकों को दिया जन्म

नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

भारत में प्रोजेक्ट चीता को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली। बोत्सवाना से लाई गई ढाई साल की मादा चीता ज्वाला 3 ने जंगल में चार शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत में चीतों की व्यवहार्य आबादी फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ज्वाला 3 बोत्सवाना से लाई गई पहली मादा चीता है, जिसने भारत में शावकों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक क्षण है और देश में चीतों की आबादी को फिर से स्थापित करने केप्रयासों को मजबूती देता है।

COP31 वार्ता में बड़ा बदलाव, नए मसौदे में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती का उल्लेख नहीं

नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में वार्ता के अंतिम चरण के बीच गुरुवार को जारी नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख हटा दिया गया। सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना निर्धारित है और इससे पहले करीब 200 देशों के बीच समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। नए मसौदे में सोमवार को जारी पहले प्रारूप की तुलना में कई प्रमुख मुद्दों पर प्रावधानों को कमजोर किया गया है या हटा दिया गया है। इनमें जीवाश्म ईंधन, बिजली के उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए वित्तीय सहायता जैसे मुद्दे शामिल हैं। पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से जुड़ी दो बातें शामिल थीं, जिनमें इसके इस्तेमाल को सीमित करने का उल्लेख था। नए मसौदे से इन दोनों संदर्भों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद के लिए 120 अरब डॉलर के वित्तीय लक्ष्य का जिक्र भी हटा दिया गया है।

जलवायु संगठनों ने जताई चिंता

जलवायु और ऊर्जा पर काम करने वाले थिंक टैंक पावर शिट अफ्रीका के निर्देशक मोहम्मद अडो ने नए मसौदे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सप्ताह की शुरुआत में जारी मसौदे से पीछे हटने जैसा है। उनके मुताबिक, यदि यही प्रारूप अंतिम समझौते का आधार बना तो सम्मेलन के पास दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं होगी।

हालांकि, सम्मेलन की साझा अध्यक्षता कर रहे तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने मसौदे में बदलाव का बचाव किया है। उनका कहना है कि इस वर्ष की बैठक का उद्देश्य पहले किए गए वादों को दोहराने के बजाय उन्हें लागू करने पर ध्यान देना है। COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने कहा कि वह इसे पीछे हटने के रूप में नहीं देखते। उनके मुताबिक, बार–बार एक ही चर्चा दोहराने के बजाय पहले से तय कदमों को आगे बढ़ाना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के COP31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने कहा कि सोमवार को जारी शुरुआती मसौदा जानबूझकर व्यापक रखा गया था, ताकि बातचीत आगे बढ़ने के साथ विकल्पों को सीमित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देशों के बीच सहमति के दायरे में सबसे महत्वाकांक्षी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर पहले भी बनी थी सहमति

वर्ष 2023 में COP28 के दौरान देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इसके बाद हुए जलवायु सम्मेलनों में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट या महत्वाकांक्षी बनाने पर सहमति नहीं बन सकी।

नए मसौदे में पहली बार किसी COP के मुख्य निर्णय में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने का अनुमान है।

मसौदे में कहा गया है कि देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु के प्रति लचीले विकास की दिशा में वैश्विक बदलाव अब अपरिवर्तनीय है। इसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि, ग्रीनपीस के COP31 प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जैस्पर इन्वेंटर ने आशंका जताई कि ऐसी तकनीकों का उल्लेख जीवाश्म ईंधन उद्योग को उत्पादन बढ़ाते रहने का रास्ता दे सकता है।

2035 तक बिजली की खपत में 35% हिस्सेदारी का प्रस्ताव

गुरुवार के मसौदे में बिजली की वैश्विक ऊर्जा खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है। फिलहाल यह हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत है। समर्थकों का कहना है कि इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। तुर्किये ने '35 बाय 35? लक्ष्य प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक करीब 75 देशों ने ही इसका समर्थन किया है। इससे पहले के मसौदे में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसे लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत होगी।

समयसीमा के बाद भी जारी रह सकती है वार्ता

COP31 का समापन शुक्रवार को होना निर्धारित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में करीब 200 देशों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा से 24 घंटे या उससे अधिक आगे तक चली है। देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना जरूरी है, लेकिन इसे हासिल करने के तरीके, इसके लिए वित्तीय जिम्मेदारी और कार्रवाई की गति को लेकर मतभेद बने हुए हैं। क्रिस बोवेन ने कहा कि समझौते तक पहुंचने के लिए वह रातभर विभिन्न देशों के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे में सम्मेलन की समयसीमा नजदीक आने के साथ वार्ता देर रात तक जारी रहने की संभावना है। (इनपुट–रॉयटर्स)

दुनियाभर में आज मनाया जा रहा है विश्व टेलीविजन दिवस, जानें कब शुरू हुआ देश का पहला टीवी चैनल

नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

आज 21 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जा रहा है। आज भी टेलीविजन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना हुआ है, भले ही स्क्रीन साइज और स्वरूप बदल गए हों और लोगों के वीडियो कंटेंट उपभोग के लिए नए–नए प्लेटफॉर्म्स बढ़े हों, बावजूद इसके वैश्विक स्तर पर टेलीविजन सेट के इस्तेमाल की संख्या लगातार बढ़ी है।

विश्व टेलीविजन दिवस को मनाए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सम्बन्धित प्रस्ताव को 17 दिसंबर 1996 को पारित किया गया था। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र ने 21 व 22 नवंबर 1996 को वर्ल्ड टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। इसी के चलते महासभा ने विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया था।

शुरूआती एकतरफा संचार के दौर के बाद आज का टेलीविजन काफी इंटेरैक्टिव हो चुका है। साधारण टेलीविजन से विकसित होकर आज के स्मार्ट टीवी ने इंटरनेट से कनेक्ट होकर वीडियो इंटेरैक्शन यानी बहुआयामी संचार को लोगों तक पहुंचाया है। आज का टेलीविजन टेलीविजन मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव कंटेंट की एक विस्तृत सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराता है, जैसे स्ट्रीमिंग वीडियो, संगीत और इंटरनेट ब्राउजिंग। विभिन्न सोशल मीडिया पर वीडियो प्लेटफार्मों से कंटेंट के उपभोग में बदलाव और लगातार विकसित हो रही तकनीक के बावजूद, टीवी अभी भी एक महत्वपूर्ण संचार का साधन बना हुआ है।

कहा जाता है कि टेलीविजन का आविष्कार एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने साल 1924 में किया था। इसके बाद साल 1927 में फार्न्सवर्थ ने दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण किया,वर्किंग टीवी का आविष्कार होने के बाद इसे 01 सितंबर 1928 में प्रेस के सामने पेश किया गया। शुरुआत में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1928 में जॉन लोगी बेयर्ड ने कलर टेलीविजन का आविष्कार किया। हालांकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत साल 1940 में हुई थी।

भारत में टीवी का सफर आजादी के बाद शुरू हुआ, इसमें यूनेस्को की अहम भूमिका रही। यूनेस्को की मदद से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत टीवी की शुरुआत हुई और आकाशवाणी भवन में टीवी का पहला ऑडिटोरियम भवन बना, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किया शुरुआत में टीवी पर नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार, ट्रैफिक रूल्स, स्वास्थ्य आदि विषयों पर सप्ताह में दो बार एक घंटे के कार्यक्रम चलाए जाते थे। 1972 में मुंबई और अमृतसर में टीवी की सेवाएं पहुंच गईं और 1975 तक भारत के 7 शहरों में इसकी सेवाएं शुरू हो गईं। 1980 तक टीवी देश के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका था। वहीं भारत में पहला कलर्ड टीवी 15 अगस्त 1982 में आया।

भारत के पहले टीवी सीरियल की बात करें तो 'हम लोग' नामक सीरियल से शुरुआत हुई थी। इस सीरियल को फिल्म अभिनेता अशोक कुमार ने बनाया था। इस सीरियल में मनोज पाहवा, सीमा पहवा, दिव्या सेठ शाह, सुषमा सेठ, राजेश पुरी, विनोद नागपाल, लवलीन मिश्रा, जयश्री अरोड़ा जैसे कई कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। इस सीरियल का आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर 1985 को टेलीकास्ट हुआ था। इस सीरियल ने उस समय खूब वाहवाही बटोरी थी। इसके बाद धीरे–धीरे टीवी पर कई अन्य सीरियल्स के प्रसारण का भी सिलसिला शुरू हो गया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की मजबूत शुरुआत

नई दिल्ली, 20 नवम्बर।

भारत ने बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के समय 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए थे। केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

भारत की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। शुरुआत धीमी रही, लेकिन एक बार लय मिलने के बाद भारतीय ओपनरों ने मैदान के चारों ओर रन बनाए। जायसवाल बेहद आक्रामक रहे। बाएं हाथ का यह युवा सलामी बल्लेबाज शतक से चूक गया। जायसवाल 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल को मैट हेनरी ने आउट किया। आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 27.5 ओवर में 130 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी।

केएल राहुल 116 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए पडिक्कल 35 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 29 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर से अभी भी 209 रन पीछे है।